

every endeavour but the response from Pakistan is not good.

Shri Hem Barua: In pursuance of the Tashkent Agreement a conference of the Commerce Ministers of India and Pakistan was held in Rawalpindi. Is it not a fact that in that conference a decision was taken to release the goods and to lift the ban on trade, if so, by failing to do it, has not Pakistan violated the Tashkent Agreement and the decision arrived at in that conference at Rawalpindi?

Shri Dinesh Singh: It is true that Pakistan is not fulfilling its obligations under the Tashkent Agreement.

Shri Hem Barua: What is this reply? We know that Pakistan is not fulfilling its obligations. What steps are they taking to bring Pakistan to a reasonable frame of mind in the light of the Tashkent Agreement?

Shri Dinesh Singh: As the House knows, it is a Declaration and not an agreement and it is a much bigger question.

Shri Bal Raj Madhok: Is it a fact that after the Tashkent Declaration Pakistan has stopped payment of those bargains which had taken place earlier, say for example the sale of Dalmia Cement Mills and other things and that they have stopped every payment due to India in the form of remittances, bonuses, etc and, if so, may I know whether any reciprocal action has been taken by India to stop all payments of shares and other things due to Pakistan?

Shri Dinesh Singh: So far as payments agreement is concerned, I shall have to enquire from my colleague in the Finance Ministry as to what the exact position is about our side. So far as I remember, Pakistan has not been fulfilling its obligations and I am sure that this point must have been borne in mind.

Shri Bal Raj Madhok: Sir, here is a question which is very much related to this. When the hon. Minister comes here, he should know what type of

questions can be asked and he should come prepared for them. The Finance Minister is not here. Who are we to know about it? This is a relevant question connected with the question that has been asked.

Shri Indrajit Gupta: The reports have appeared that there are a number of Pakistani commodities which are being re-exported through third countries, say, for example, raw jute, to India and in some cases vice versa also. May I know whether the Government has any information on this subject?

Shri Dinesh Singh: We import some items from different countries. I cannot say what the origin of these items is. Perhaps some country may have imported from Pakistan and given to us. The hon. Member knows very much that this is being practised by a number of countries: what is called, the Swiss trade.

पुस्तकों का आयात

+

* 996 श्री प्रकाशवीर शारदा:
श्री रघुवीर सिंह शारदा:

क्या बालिस्थ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत में साहित्य की बहुत सी पुस्तकों का आयात किया जा रहा है,

(ख) क्या यह भी सच है कि विज्ञान और अन्य उपयोगी विषयों की पुस्तकों के साथ-साथ बहुत सी यौन सम्बन्धी पुस्तकों का भी आयात किया जा रहा है,

(ग) ऐसी पुस्तकों पर प्रतिबंध कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जाती है, और

(घ) क्या सरकार ऐसी पुस्तकों के आयात पर रोक लगाने का विचार कर रही है?

वाणिज्य मंत्री (श्री विनेश सिंह) : (क) से (ब), एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

वर्तमान आयात नीति के अन्तर्गत पुस्तकों के सुस्थापित आयातकों को उनके सर्वोत्तम वर्ष के आयात के 150 प्रतिशत तक का कोटा दिया जाता है। साहित्यिक और वैज्ञानिक पुस्तकों के लिए अलग अलग कोटे नहीं हैं, परन्तु पत्र-पत्रिकाओं तथा कथा साहित्य के लिए कोटा लाइसेंसों के केवल 40 प्रतिशत भाग का प्रयोग करने की अनुमति है एवं इनके प्रतिरिक्त यह भी शर्त है कि कथा साहित्य की पुस्तकों के आयात के लिए कुल कोटे के केवल 10 प्रतिशत भाग का ही प्रयोग किया जाए।

2. तकनीकी पुस्तकों, विधि सम्बन्धी सन्दर्भ पुस्तकों अथवा चिकित्सा व्यवसाय, वैज्ञानिक गवेषणा, औद्योगिक प्रीक्ष्या सम्बन्धी पुस्तकों के आयात के लिये अनु-पूरक लाइसेंस देने की व्यवस्था है।

3. 1964-65, 1965-66 और 1966-67 (अप्रैल-फरवरी) में आयात की गई पुस्तकों का कुल मूल्य क्रमशः 3.29 करोड़ ₹०, 2.76 करोड़ ₹० तथा 3.10 करोड़ ₹० था। इस अवधि में केवल 11 लाख रुपया, 7 लाख ₹० और 16 लाख ₹० मूल्य की पत्र-पत्रिकाओं का आयात हुआ था।

4. अस्सील तथा अवाञ्छनीय पुस्तकों के आयात पर रोक लगी हुई है और सीमा शुल्क अधिकारी के लिये इसे कार्यान्वित करना अपेक्षित है। पुस्तकों के आयात के लिये तन्नाम लाइसेंस इस शर्त पर दिये जाते हैं कि वे अवाञ्छनीय प्रकार की पुस्तकों, विनोद पत्रिकाओं तथा साहित्य एवं पत्रिकाओं के लिये वैध नहीं होंगे। अस्सील तथा अवाञ्छनीय प्रकार की अनेक पत्रिकाओं पर रोक सभा ही गई है।

श्री प्रकाशवीर शारदा : : अध्यक्ष महोदय, विवरण में पिछले तीन वर्षों के जो आंकड़े दिये गये हैं उन से लगता है कि पिछले 20 वर्षों में लगभग सबा तीन करोड़ रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से इस प्रकार की पुस्तकों का आयात हुआ, जो सब मिला कर 75 करोड़ रुपये की बताई जाती है। अंग्रेजी राज्य के समय में भी इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी पुस्तकों का आयात नहीं होता था, विशेष रूप से कथा रें साहित्य, पत्र-पत्रिकाओं का जब कि अब भारत सरकार के सामने इतनी विदेशी मुद्रा की कमी है तो क्या किसी प्रकार से इस आयात को कम किया जा सकता है। क्या इस नीति पर विचार किया गया है या सरकार ज्यों का त्यों इस नीति को जारी रखना चाहती है ?

श्री विनेश सिंह : माननीय सदस्य जानते हैं कि जब से अंग्रेजी सरकार यहां से गई है तब से इस देश में पढ़ाई बहुत ज्यादा बढ़ी है, यहां पर अब बहुत ज्यादा लोग पढ़ते हैं इसलिये किताबों को बाहर से मंगाने की जरूरत पड़ती है। बहुत दूरा इस सदन में भी कहा गया है कि किताबों मंगाना खुला छोड़ देना चाहिये, ताकि ज्यादा से ज्यादा किताब हमारे यहां भावें। यह बात सही है कि हमको देखना चाहिये कि गलत तरह की किताबों पर विदेशी मुद्रा न बरबाद की जाये, उस के लिये हम निरन्तर कोशिश करते रहते हैं।

Shri N. K. Somani: What is wrong with sex books?

Shri Hem Barna: Whether sex books are good or bad who is going to judge?

श्री प्रकाशवीर शारदा : इस प्रश्न के भाग (ब) के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा है कि जो इस प्रकार की अस्सील पुस्तकें हैं, विशेषकर जो नई पीढ़ी के युवकों के लिये हानिकारक हैं, उनके आयात पर ज़रूर

सरकार ने कानूनी प्रतिबन्ध लगा रखा है, लेकिन दिल्ली के चौराहों पर जहाँ कि यह विदेशी साहित्य बिकता है वहाँ प्रायः कर के इस प्रकार की पुस्तकों और इस प्रकार के दूसरे साहित्य की पूरी तरह से भरमार इन दुकानों में देखी जा सकती है। क्या सरकार ने इस बात की जानकारी प्राप्त की है कि कहीं उन पुस्तकों की भाँड़ में इस प्रकार की अश्लील पुस्तकों का आयात तो प्रारम्भ नहीं हो रहा है जो देश की नई पीढ़ी को बिगाड़ने में सहायक हो रही है? अगर सरकार ने इस प्रकार की जानकारी प्राप्त की है तो इस प्रकार की पुस्तकों का आयात करने वाले कुछ व्यक्तियों के खिलाफ क्या सरकार ने किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की है?

श्री विनेश सिंह: मेरे जगल से कोई ऐसी जांच इसमें नहीं हुई है। लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि दिल्ली में ऐसी किताबें बिकती हैं जो हमारी बैंड-लिस्ट में हैं, वे अगर बिकनी हैं, तो मैं उसकी जांच करवाने की कोशिश करूँगा। मैंने खुद नहीं देखा है क्योंकि मैं उधर नहीं गया हूँ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: हर चौराहे पर बिकती हैं।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री: पश्चिमी विचारधारा के प्रभाव के कारण आजकल हम सम्बन्ध में दृष्टिकोण बड़ी तेजी से बदल रहा है। मैं मंत्री महोदय ने पूछना चाहता हूँ कि कौन कौन अश्लील है या नहीं है: इसके लिये उन्होंने क्या तरीका या मानदण्ड निर्धारित किया है? साथ ही इसके लिये क्या उपाय या सतर्कता बरती जा रही है ताकि इस प्रकार का साहित्य कच्ची उम्र के शिशुओं के हाथ में न जाय और उन पर कुप्रभाव न पड़े?

श्री विनेश सिंह: यह एक ऐसा विषय है, जिस पर कोई एक मत नहीं हो सकता

है। जब यह सवाल हो रहा था आप ही की बगल से कई भाषाओं, अख्यक महोदय, आपने सुनी होंगी जो इसके विपरीत थी, फिर भी जैसे माननीय सदस्य कह रहे हैं, हम तो इसकी कोशिश करते हैं। जिन अखबारों या किताबों में कोई भद्दे तरह की तस्वीरें छपती हैं या जो बाहिरा तौर पर ऐसी दिखती हैं जिनकी भद्दा ज़रूरत नहीं है, उन पर विदेशी मुद्रा का बर्च होना हम रोक्ते हैं। अब इसकी क्या कसौटी हो। मैं नहीं समझता कि हमको इस में कुछ ज्यादा पढ़ना चाहिये। कोशिश यह करनी चाहिये कि आसानी से जो रोकी जा सकती है, उन को रोके।

Shri Hem Barua: I have a very important question to ask.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: अख्यक महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं व्यवस्था यह चाहता हूँ कि शास्त्री जी का जो प्रश्न था, वह बड़ा स्पष्ट था। अश्लील की व्याख्या क्या है वह इसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन सरकार अपने मस्तिष्क से किस को अश्लील समझती है और किस साहित्य पर रोक लगाती है उन के सम्बन्ध में कम से कम सरकार अपना मत बताये।

Mr. Speaker: I think, the Minister has already answered.

Shri Chintamani Panigrahi: May I know whether, under the various cultural agreements with different countries, India is also exporting books from this country and among the imports which we are having, which language publications top the list of those imports?

Shri Dinesh Singh: I think, the bulk of the import of books is in English.

Shri Chintamani Pasigrahi: One part of my question has not been answered. I wanted to know whether India is exporting books to different countries.

Shri Dinesh Singh: Yes, we also send our books

Shri Pileo Mody: I have read these books on sex that come from abroad and I find them to be more educative than the text-books that the Government produces, particularly on Geography. I would like to ask the Minister what steps he is taking to destroy those books.

Mr Speaker · Mr Madhu Lamaye

श्री मधु लामये: यह सवाल कितनों की धारणात के बारे में है और इन्होंने यह कहा है—

"Import of obscene and undesirable books is banned and the Customs are required to implement it"

तो कम से कम कस्टम वाले इस की भी जानकारी जरूर रखते होंगे कि क्याई जरूरी है किताबें लेकिन किताबें नहीं आती, उन्हीं जगह रुकी जाती है। 1 जुलाई को मैंने उस का उल्लेख किया था। 7 दिन हो गये—क्या मंत्री महोदय ने इसकी जानकारी हासिल की है कि ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो किताबों का साइसेस लेते हैं, दस्तावेज आदि बैंको के द्वारा आते जाते हैं, लेकिन किताबें नहीं आती हैं, रुकी जाती है और जो विदेशी मुद्रा बच जाती है, उस में बढ़िया और दूसरे सामान सस्ते में मगवाते हैं यानी रुपये का भास दो आने मूल्य में।

श्री विनेश सिंह: जी हाँ, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने चिन्त किया था और वह आप के लिये मैंने कह दिया था।

श्री किमुति शिख: क्या वह सही है कि मुद्रा बचपूरकन के लिए विदेशी पुस्तकों के बाव, जैसे किताबों की फाइलों की और एकोनमिक्स की किताबों की कीमतों बहुत ज्यादा बढ़ गयी हैं और क्या सरकार ऐसा तोफ रही है कि बाहर से ऐसी किताबों के बीच एकीकृत नवाये जायें ताकि इस देश के गरीब विद्यार्थी को साइस पड़ते हैं, वैदिकता कानिसेज के पड़ते हैं या एकोनमिक्स पड़ते हैं उन्को जब किताबों को बादीय में सलू-लियत हो सके ?

श्री विनेश सिंह: जी हाँ, कमाने कसे की इसमें ज्यादा ध्यानदा घमना पड़ते हैं कि जो उनको विदेशी मुद्रा का साइसेस निम्न है उससे वह उन पुस्तकों के सस्ते एडीकन्स मसके ताकि उन पुस्तकों को वह ज्यादा बेच सकें।

श्री किमुति शिख: अध्यक्ष महोदय, के पूछना चाहता हू कि सरकार इसके लिए कुछ कार्यवाही करदे की सोच रही है तर्कि हमारे देश के गरीब विद्यार्थी भी उन कीको को पसकें ?

श्री विनेश सिंह: उसके लिए तो अध्यक्ष महोदय, क्या खपाई का इतजाम करना है जिसके बारे में मैं समझता हू कि यहा एचुकेसन मिनिस्टरी ने कुछ उसके लिए कदम उठाया है।

Shri Tenneti Viswanatham: Reverting to the obscene books, what is the opinion of the hon Minister about *Lady Chatterley's lover*? Has he banned it?

Shri Pileo Mody: Is he asking for his personal opinion or his official opinion?

Shri Tenneti Viswanatham: I am asking for the Government's opinion. Has the book been banned and if it has been banned, why is it found in the book-shops here?

Shri Dinesh Singh: No.

Shri Surendranath Dwivedy: What is the meaning of 'No'? Has it been banned or not?

श्री रघुवीर सिंह: हमारे देश में कुछ ऐसी संस्थाएँ, कंसोसियेन्स और यूनिवर्स हैं जिनका कि काफ़ी एंटी नेशनल और एंटी सोशल प्रोग्राम चलता है और वह देश को बड़ी हानि पहुँचाती हैं। रियल के तौर पर उन के पास बहुत ज्यादा तादाद में बाहर के किताबें आती हैं और जैसे-जैसे और-और वहाँ-वहाँ उनकी बेचते हैं और इस तरह से देश के खिलाफ़ एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ चलाना चाहते हैं तो क्या मिनिस्टर साहब के नोटिस से ऐसी यूनिवर्स हैं जो यह काम करती हैं और क्या वह उनके इम्पोर्ट के लिए कोई बात सोचते हैं?

श्री विमेश सिंह: अगर वह बगैर पैसे के आती हैं तो जाहिर है कि उसमें कोई विदेशी मुद्रा खर्च नहीं होती है। यहाँ तो वह विदेशी मुद्रा के हिस्सा में देकर रहे थे।

Shri Swell: The hon Minister has said that certain types of books should not be imported into the country. I would like to know whether he has some kind of machinery or he has developed any kind of process to sort out these books and decide which books should be brought into the country and which books should not be brought, and if he has that kind of machinery, whether this machinery has been given the authority to decide what books the people of this country should read and what they should not read?

Shri Dinesh Singh: So far as the books are concerned, they are decided by the Minister of Education and the Ministry of Home Affairs in the case of anti-national books. So far as the magazines are concerned which are banned, they have been decided by the Controller-General of Imports and Exports.

An hon. Member: There is no Controller-General of imports and exports but only a Chief Controller.

Shri D. C. Sharma: The universities and colleges in India have been complaining for the last two years that they cannot get reference books which they need and they cannot get journals which they need and they cannot get books of use to the students and professors because of the restrictive nature of the import policy of the Government of India, which is of a very wrong kind, and which, so to say, works against the best interests of this country.

Shri Dinesh Singh: I am glad the hon Member has pointed this out. I may mention to the House that we have increased the quota of import for books this year from what it used to be before. In 1965-66 it had come down to 50 per cent of what it was in 1963-64. Now, we have not only restored it but actually increased it to 150 per cent. Apart from this, libraries and other institutions are freely allowed to import books on the basis of actual use, such as technical books for their requirements.

Uneconomic Railway Lines

+

*997. **Shri S. C. Samanta:**

Shri Yashpal Singh:

Shri A. K. Kisku:

Shri S. N. Maiti:

Shri Tridib Kumar Chaudhuri:

Shri Vishwa Nath Pandey:

Shri Y. A. Prasad:

Shri Ram Kishan Gupta:

Shri E. K. Sinha:

Shri N. K. Saughi:

Shri Parthasarathy:

Shri Hem Raj:

Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is proposed to scrap certain uneconomic railway lines;